## fogxkoykdu

इस प्रतिवेदन में एक समीक्षा सहित 33 कंडिकाएँ हैं जिनमें 206.42 करोड़ रुपये का कर, ब्याज आदि नहीं/कम लगाये जाने से सम्बन्धित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

### I. lkekU;

वर्ष 2006–07 के लिये बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 23,083.19 करोड़ रुपये थी। कर राजस्व के 4,033.08 करोड़ रुपये और कर भिन्न राजस्व के 511.28 करोड़ रुपये को मिलाकर, राज्य सरकार ने कुल 4,544.36 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से 18,538.83 करोड़ रुपये (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्साः 13,291.72 करोड़ रुपये और सहायता अनुदानः 5,247.11 करोड़ रुपये) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राज्य सरकार, कुल राजस्व का केवल 20 प्रतिशत ही सृजित कर सकी।

*¼dfMdk 1-1-1½*

वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2006–07 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 607.01 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम निर्धारण/हानि के 4,643 मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2006–07 की अवधि में सम्बद्ध विभागों ने 746 मामलों में अन्तर्निहित 237.82 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया।

*¼dfMdk 1-10½*

दिसम्बर 2006 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2007 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 3,126 एवं 16,835 थी जिसमें 3,273.56 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे। 2,237 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

*¼dfMdk 1-11½*

### II- fcØh] 0;kikj vkfn ij dj

एक वाणिज्यकर अंचल में एक व्यवसायी के बिक्री राषि में 125 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क सम्मिलित नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 21.87 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

*¼dfMdk 2-2-1-1½*

एक वाणिज्यकर अंचल में, एक व्यवसायी के मामले में 72.33 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं का अन्तर्राज्यीय बिक्री यद्यपि घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित नहीं था, कर का आरोपण कम दर पर लगाया गया था। इसके फलस्वरूप 9.64 करोड़ रुपये के कर का अवनिर्धारण हुआ।

*¼dfMdk 2-3-1½*

10 वाणिज्यकर अंचलों में 35 व्यवसायियों द्वारा 47.69 करोड़ रुपये मूल्य के बिक्री/क्रय राषि छिपाये जाने के फलस्वरुप 8.04 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

*¼dfMdk 2-4½*

एक वाणिज्यकर अंचल में 46.01 करोड़ रुपये के छूट का गलत अनुमति दिये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त कर एवं अधिभार सहित 1.79 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

*¼dfMdk 2-5-1½*

## III- jkT; mRikn

सात उत्पाद जिलों में खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2002–03 से 2005–06 के दौरान न्यूनतम गारंटी कोटा का उठाव नहीं किया था, जिसके कारण 47.98 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

*¼dfMdk 3-2-1½*

10 उत्पाद जिलों में 219 देषी षराब, 153 मसालेदार देषी षराब एवं 75 भारत निर्मित विदेषी षराब दुकानों की बन्दोबस्ती एक से 11 महीनों की समाप्ति के बाद की गई थी, जिसके फलस्वरूप 11.85 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

*¼dfMdk 3-3-1½*

## IV- ekVj okguksa ij dj

आठ जिला परिवहन कार्यालयों में 95 परिवहन वाहनों को कर के अद्यतन भुगतान को सुनिष्चित किये बगैर योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2002 एवं जुलाई 2006 के बीच की अवधि के लिये 2.74 करोड़ रुपये (अर्थदण्ड सहित) के कर की वसूली नहीं हुई।

*¼dfMdk 4-2½*

30 जिला परिवहन कार्यालयों में जुलाई 2002 से जून 2006 के अवधि से सम्बन्धित 1,198 वाहनों के 27.38 करोड़ रुपये के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही सम्बंधित कर प्राधिकारियों द्वारा बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई की गई थी।

*¼dfMdk 4-3½*

## V- vU; dj çkfIr;k¡

रैय्यतों द्वारा कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने पर व्यावसायिक लगान के निर्धारण नहीं होने के फलस्वरुप 1.18 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

*¼dfMdk 5-2½*

वर्ष 2001–02 से 2004–05 के दौरान तीन वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित तीन व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित वस्तुओं के आयातित मूल्य को छिपाये जाने के परिणामस्वरुप आरोप्य न्यूनतम अर्थदण्ड सहित 39.60 लाख रुपये के प्रवेष कर का कम आरोपण हुआ।

*¼dfMdk 5-4½*

## VI- dj fHké çkfIr;k

“[kku ,oa [kfutksa ls çkfIr;k” की एक समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चला :

खान निदेषक द्वारा दोषी ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किये जाने का अनुश्रवण के लिए जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा संधारित ईंट भट्ठा रजिस्टर के समीक्षा की प्रणालियों में कमी के कारण 7.89 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

*¼dfMdk 6-2-7½*

जिला खनन पदाधिकारियों/सहायक खनन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्रों के ब्योरे के सत्यापन को खान निदेषक द्वारा की गई समीक्षा को सुनिष्चित करने की प्रणाली में कमी के कारण कार्य संवेदकों के विरूद्ध 12.79 करोड़ रुपये के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

*¼dfMdk 6-2-8½*

कोषागार आँकड़ों के साथ विभागीय आँकड़ों का मिलान करने में जिला खनन पदाधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप 1.70 करोड़ रुपये का दुर्विनियोजन हुआ।

*¼dfMdk 6-2-10½*

आठ जिला खनन कार्यालयों में 2001–02 से 2006–07 के दौरान 44 पत्थर के खानों और बालू घाटों के बन्दोबस्ती दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप 3.60 करोड़ रुपये के मुद्रांक शुल्क का नहीं/कम वसूली हुई।

*¼dfMdk 6-2-12½*

पाँच जिला खनन कार्यालयों में 9.64 करोड़ रुपये रक्षित मूल्य के 118 बालू घाटों के अबन्दोबस्त रहने के फलस्वरूप 8.95 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

*¼dfMdk 6-2-13½*

सात प्रमण्डलों में 2001–02 से 2005–06 के दौरान खरीफ का 2.11 लाख हेक्टेयर एवं रबी का 2.17 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हेतु खतियानी तैयार नहीं की गई थी तथा जलदर के 8.56 करोड़ रुपये के लिये माँग सृजन एंव संग्रहण हेतु उन्हें सम्बन्धित राजस्व प्रमण्डलों को नहीं भेजा गया था।

*¼dfMdk 6-3½*

दो वन प्रमण्डलों में 14.92 हेक्टेयर वन भूमि के अतिक्रमणकारियों से 86.56 लाख रुपये की वसूली नहीं की गई थी।

*¼dfMdk 6-6½*